श्री नितिश कुमार : यह तो स्पष्ट है टीश्यू कल्चर उसका पार्ट है । टीश्यू कल्चर में भी एलोकेशन किया जा रहा है और उसके लिए भी अलग से सब कुछ अनुसंधान के कार्य चल रहे हैं ।

SHRI P.R. KUNJACHEN: Sir, tissue culture technique is a new branch of development. When new research is being conducted, it is very difficult to get results immediately. But at the same time this research is a must and it has to be developed. So, considering the importance of this matter, whatever result is achieved so far, it should be brought into the field of agriculture. So, I want to know whether the Government will take the initiative to continue the research and also see that it is made applicable in the field. It should not remain in the universities alone. Then it will not be giving any result. It should be brought to the field. For that, the Government should take action. It should be co-related. I want to know whether the Government will take action in this regard.

श्री नितिश कुमार : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने ठीक फरमाया है । सरकार यही चाहती है और यही कर रही है ।

श्री छोटू भाई पटेल : सर, ट्रांसफर ऑफ टैक्नोलॉजी फारमर्स में सरक्यूलेट होती है या नहीं होती है या कम होती है, तो इसके बारे में सरकार क्या कार्रवाई करना चाहती है ?

श्री नितिश कुमार : ट्रांसफर आफ टैक्नोलोजी के बहुत से कार्यक्रम चल रहे हैं इस देश में । कृषि विज्ञान केन्द्र है या लैब टू लैंड प्रोग्राम है---कई प्रोग्राम चलते हैं जिससे कि जो एक्यूअल रिसर्च से एचीवमेंट होता है उसको जमीन पर उतारा जा सके । ऑन फार्म डेमोन्स्ट्रेशन होता है, एडॉप्टिव डेमोन्स्ट्रेशन होता है, ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन होता है, ये सारे कार्यक्रम कृषि विभाग के विभिन्न महकमों के द्वारा चलाए जाते हैं ।

SHRI J. S. RAJU: Mr. Chairman, Sir I want to know whether this plant tissue culture has been initiated in Tamil Nadu and if not, why not.

श्री नितिश कुमार : तमिलनाडु के बारे में मैं इनको अलग से सूचना दे दूंगा कि क्या एक स्टेट की प्रगति है । यह सभी जगहों की मिलाकर के सूचना दी है ।

MR. CHAIRMAN : Question No. 344.

**Excessive payments for purchase of electrical equipment by the Eastern Railway**

*344. SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE:
SHRI PRAMOD MAHA-JANt

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether in the second week of April last several places in Bihar and Calcutta were raided and documents were seized, which established that excessive payments of crores of rupess were mile to two or three 'favourite companies' by the Eastern Railway in the purchase of electrical equipment, generating large-scale kick-backs, as reported in the Indian Express, dated 13th April, 1990;

(b) if so, what are the facts and findings in this regard; and

(c) the nanus of the officials and suppliers involved in this case?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI AJAY SINGH): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the Sabha.

The question was actually asked on the floor of the House by Shri Pramod Mahajan.

**Statement**

(a) to (c) The Central Bureau of Investigation registered for investigation 5 cases on 28-03-1990, against 4 Eastern Railway officials and 12 private firms, for alleged procurement of electrical equipments at high rates, and making procurement in excess of actual requirements, resulting in approximate loss of Rs. 57- 50 lakhs to the Railways. Searches were conducted at 18 places by the CBI, simultaneously, on 11-04-1990, in Bihar and Calcutta during which 212 incriminating documents were seized. The disclosure of names at this stage will adversely affect the CBI investigation.

**श्री प्रमोद महाजन** : सभापति जी रेलवे के लिए माल की खरीद में बहुत भ्रष्टाचार होता है । पकड़े कम जाते हैं और सजा उससे भी कम लोगों को होती है और इसीलिये भ्रष्टाचार और भी बढ़ता जाता है, उस पर नियंत्रण नहीं होता है । अब इस मामले में पूर्व रेल के 4 अधिकारी और 12 निजी फर्म शामिल हैं और सरकार इनके नाम बताने से इंकार कर रही है । ये अधिकारी, जबकि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, तो स्वाभाविक रूप से निलंबित हुए होंगे, उनको इस संबंध में सूचना गई होगी । समाचार पत्रों में भी इस संबंध में खबरें छपी हैं। अब यह सरकार अपने आपको खुली सरकार कहती है, तो इस दृष्टि से मैं क्या रेल मंत्री से यह अपेक्षा कर सकता हूं कि वह प्रशासनिक तरीके से उत्तर न देते हुए इन रेलवे के भ्रष्ट अधिकारियों और उनके साथ जिनकी सांठ-गांठ है, ऐसे व्यापारियों के नाम सदन को बताकर भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करेंगे ?

SHRI AJAY SINGH: Mr. Chairman, Sir, while it is correct that in a department like the Railways, which is one of the big purchasers in the country, there is corruption to an extent, as far as the question of disclosing the names is concerned, a C.B.I, enquiry is going on. It is felt that publicising their names would adversely affect the C.B.I, investigations. But if the hon. Member wants to know further details, if he cimes to me I can give him the details.

**श्री प्रमोद महाजन** : महोदय, मैं यह नहीं समझ सकता कि मुझे अगर नाम बताने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं है तो सारे सदन को बताने में क्या आपत्ति है । यह सदन तो मुझ से अधिक शक्तिशाली और सर्वोच्च है । मैं तो इस सदन का एक छोटा सा सदस्य हूं ।

**श्री विठ्ठलराव माधवराव गाधव** : यह तो हाउस में बोल रहे हैं और मंत्री जी कहते हैं कि प्राइवेट में बताएंगे । यह तो सदन का अपमान है । वह कहते हैं प्राइवेट में बताएंगे . . . (व्यवधान)

SHRI SURESH KALMADI : They are telling the B.J.P. privately many things.

**श्री राम अवधेश सिंह** : इसका मतलब यह है कि सरकार को कुछ मिलीभगत है।

**श्री प्रमोद महाजन** : सभापति जी, इसमें मैं आपसे संरक्षण चाहूंगा । यह जो चार रेल अधिकारी निलंबित हुए, उनको सूचना चली गई होगी, उनके आस-पास के लोगों को पता चल गया होगा । जब 18 जगह छपे पड़े हैं तो सब जगह लोगों को पता चला । अब आखिर सरकार नाम क्यों छिपाना चाहती है? क्या कुछ ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं जिनको सरकार संरक्षण देना चाहती है? अभी जो रेल मंत्री के सहायक हैं उन्होंने तो कह दिया कि थोड़ा सा भ्रष्टाचार तो रेल में होता ही है । उन्होंने इसे मान लिया है, यह खुली सरकार का एक नमूना है । लेकिन मैं उन अधिकारियों के नाम जानना चाहता हूं ।

**श्री सभापति** : वह पूछ रहे हैं कि जो अधिकारी सस्पेंड हुए हैं उनके नाम बताने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ।

श्री राम अवधेश सिंह : जो अपराधी थे उनके नाम बता दीजिए । नहीं बताने से लगता है कि मोल-तोल होता होगा कुछ ।

श्री सभापति : सस्पेंड अधिकारियों के नाम बता दीजिए ।

You cannot claim that this will not be in the public interest. It is a known fact. The question of suspension is a known fact.

SHRI CHHOTUBHAI PATEL : The Minister is hiding something.

SHRI AJAY SINGH : Mr. Chairma'z. Sir, investigations are going on. The names have not come out. It is incorrect to say that the names have bean publicised in the newspapers. The names have not come out.

MR. CHAIRMAN : The question which he asked was very simple. If they have been suspended, the office knows; everybody knows. Where is the question of the names not having come out ?

SHRI PRAMOD MAHAJAN : A clerk who types the orders knows, but it cannot bo make known to a Member of Parliament :

MR. CHAIRMAN : Suspension is something public. You cannot suspend a person privately.

SHRI CHATURANAN MISHRA : After all, against whom the enquiry is being conducted ?

SHRI AJAY SINGH : Actually, four people are involved. They are : Mr. R.P. Sharma, Assistant Electrical Engineer, Dhanbad, Eastern Railway ; Mr. M.C.S. Rao, Senior Electrical Foreman, Eastern Railway ; Mr. B.R. Mahto, Senior Electrical Forement, Danapur, Eastern Railway and Mr. Diwakar Singh, Senior Electrical Foreman, Eastern Railway, These are the four persons.

SHRI RAM AWADHESH SINGH : what about the big fish ?

SHRI AJAY SINGH : The enquiry is going on. We will also try and nab the big fish, if there are any.

श्री प्रमोद महाजन : सभापति जी, आधा ही जवाब मिला है । बारह फर्मों के नाम नहीं मिले हैं । मुझे लगता है जिन श्रेणी के अधिकारियों का नाम बताया गया है वह बहुत छोटे अधिकारी हैं और वह बारह फर्मों के साथ करोड़ों रुपयों का भ्रष्टाचार करने में सक्षम नहीं हो सकते । इसका अर्थ यह है कि कहीं कोई न कोई बड़े अधिकारी इसमें शामिल हैं । इस दृष्टि से मैं पूछना चाहूंगा कि रेलवे में जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा कि भ्रष्टाचार होता है, नयी सरकार आने के बाद इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिये क्या कोई विशेष कदम जो पिछली सरकार के समय चलते आये हैं वह तो होंगे ही और नहीं चलते आये हैं वह रुके होंगे, लेकिन नयी सरकार आने के बाद इस भ्रष्टाचार को, खरीद के भ्रष्टाचार को रोकने के लिये क्या कोई विशेष कदम उठाये हैं? या पिछले तरह से आगे चालू हैं ।

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीज) : सभापति जी, नयी सरकार आने के बाद हम लोग इस क्षेत्र में विशेष, प्रयास में लगे हैं । एक तो हमने रेल के सारे विजिलेंस के लोगों की दिल्ली में मीटिंग बुलायी थी और सिर्फ उच्च स्तरीय अफसरों को ही नहीं बुलाते हुए डिवीजन स्तर तक के इस काम में लगे हुए जो अफसर हैं उन सबको यहां पर बुलाया था और तीन क्षेत्रों में हम खास प्रयास में लगे हैं । पहला, जहां रेल कर्मचारियों का या रेल में किसी भी कर्मचारी का, अफसर का जनता के साथ सम्पर्क आता है और जहां पर किसी प्रकार की गड़बड़ी की सम्भावना है । दूसरे, जहां पर रेलवे में खरीददारी आदि चीजों का काम होता है, जैसे इस मसले की यहां पर चर्चा हो रही है । और तीसरा यह है कि रेलवे में कर्मचारियों को जो भर्ती, उनके तबादले आदि होते हैं जिसके बारे में भी बहुत शिकायतें हैं और जिनकी

जांच भी हो रही है तो इन क्षेत्रों में हम विशेषकर अभी प्रयत्नशील हैं और ऐसे कई मसले, यह तो अखबार में एक चीज छप गयी इसलिये इसकी आज यहां पर चर्चा है, मगर कई मसले हैं जो छपे नहीं हैं तथा उन पर अभी कार्यवाही हो रही है । हमने यहां तक देखा है कि एक चीज का दाम अगर एक रुपया हो तो पैंतीस रुपये दाम लिखाकर रेल को लूटने का काम हो रहा है और उस पर रोक लगाने में हम लोग लगे हैं ।

सभापति जी, इसके साथ हमने एक और निर्णय लिया है जिसका आदेश भी अभी डेढ़-दो महीने पहले जारी किया गया है जिसमें अगर कोई नीचे का अधिकारी या कोई नीचे का कर्मचारी पकड़ में आता हो तो केवल उसी पर कार्यवाही नहीं की जायेगी, बल्कि उसके लिये जो जिम्मेदार ऊपर के लोग हैं जिनका यह काम है कि उसके हाथ के नीचे का कर्मचारी ईमानदारी से अपना काम करता हो, यह देखना भी उसका काम है तो उस पर भी कार्यवाही की जायेगी अगर नीचे के अफसर ने या नीचे के कर्मचारी ने कोई गलत काम किया है, यदि इसका सबूत हमारे हाथ में आता हो ।

इसके साथ ही हमने यह भी एक निर्णय लिया है कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी अफसर को एक जगह पर चार साल से अधिक समय के लिये हम नहीं छोड़ेंगे और विशेषकर जो सेंसेटिव जगह हैं, जहां पर पैसे का यह सारा काम काज होता है वहां उसको रहने नहीं देंगे । मगर समस्या उसमें इतनी है कि बहुत चिट्ठियां आ जाती हैं जिसमें इन कर्मचारियों को फिर उन्हीं जगहों पर रखा जाये । इसके लिये दबाव डालने का काम तो चलता ही रहता है ।

**एक माननीय सदस्य :** क्या एम० पी० की तरफ से ?

**श्री आर्ज फर्नांडीज :** हां वह सबसे ज्यादा आती हैं और इस पर भी हम इतनी सख्ती के साथ काम कर रहे हैं । इसलिये प्रयत्न तो जारी हैं कुछ नये सिरे से ।

**श्री सभापति :** श्री जगेश देशाई :

**श्री रामअवधेश सिंह :** इसका जवाब तो नहीं हुआ . . . (व्यवधान)

**श्री जार्जा फर्नांडीज :** सभापति जी, नाम तो दे दिया है ।

**श्री जगेश देसाई :** चेयरमैन सर,

**श्री राम अवधेश सिंह :** चार उन अफसरों के नाम दिये जो छोटे अफसर हैं । जो बड़े अफसर हैं उनको नहीं बताया और जो बिजनिसमेन इंवोल्वड हैं . . . (व्यवधान)

**श्री सभापति :** क्या कर रहे हैं राम अवधेश सिंह जी । अब हमने जगेश देसाई जी को बुलाया है । जब आपका नम्बर आये तब आप पूछिएगा । जो पूछ रहा है वही आगे पूछने लगेगा तो फिर क्या मतलब हो गया ।

SHRI JAGESH DESAI : Mr. Chairman, Sir, as far as I know, the rates charged were even six times in this case. There should be internal audit department of the Railways. Have they found anything lik this ? Part (b) of my question is, you have conducted 18 searches. They have got so many documents. Were these searches made at the premises of the railway officers ? After you came to know that there 12 firms were in league with the officers, have you at least temporarily black-listed them ? I would like to know the nature of the dicuments which have been seized.

SHRI AJAY SINGH : Sir, as stated earilier, raids were conducted at 18 placed. As far as documents are concerned, they are with the CBI. As far as hon. Member's question regarding particular concerns is concerned, they will be considered for black listing automatically when, they come under this kind of senitiry.

SHRI JAGESH DESAI : No, no, so many Divisions are there. I would like to know whether they have been informed. Automatically it is never done. As far as I know when the names have been decided, these are communicated to all other Departments.

Secondly, I asked what your internal audit system is in this case.

SHRI AJAY SINGH : As far as internal audit system is concerned, there are certain categories—for example, at the DRM level and the equivalent competent authorities. Here the authority to initiate purchases upto the value of Rs. 40,000. This category of criminal activity that has come to notice concerns this level of operation where there seems to have been a large scale collusion between the various members of the railway staff.

**श्री राम अवधेश सिंह :** सभापति महोदय, मंत्री जी जो अपनी दोषी हैं..

**श्री सभापति :** प्रश्न करिये।

**श्री राम अवधेश सिंह :** हम लोग जानना चाहते हैं कि वह नाम बताने से क्यों बचना चाहते हैं। यह बात सही है कि एक कमीशन ने विदवासनी प्रसाद और जस्टिस मैथ्यू ने रेलवे के बारे में कहा है कि भ्रष्टाचार दूर हो जाए तो दस साल में लोहे की जगह चांदी की रेल की पटरी लग सकती है। यह हम लोग जानते हैं। लेकिन जो नयी सरकार आयी है इससे ज्यादा अपेक्षा थी कि कुछ सफाई होगी। लेकिन जो तीन फर्म हैं जिनका जिक्र क्वेश्चन में है वे कौन-कौन हैं और क्या उनको ब्लैक लिस्टेड करके रोकेंगे? **(व्यवधान)** उनके नाम बताइये और उनको ब्लैक लिस्टेड करेंगे या नहीं?

MR. CHAIRMAN : He wants to know the names of the firms and whether they have been blacklisted.

SHRI AJAY SINGH : As far as blacklisting is. concerned, that will be done after the enquiry. Dealings automatically stop with these firms. If the hon. Member wants to know the names of these firms, I can give the names, if that is the question. They are with me

मैं आपको नाम बता सकता हूं

**श्री राम अवधेश सिंह :** यह जब आते हैं सवालों का जवाब लेकर तो नाम लेकर क्यों नहीं आते। तीन फर्म हैं जिसके बारे में सवाल है। ये नाम लेकर नहीं आते इसमें जरूर कुछ है। सरकार का उस ब्लैक लिस्टेड होने वाली फर्म के साथ कुछ तालमेल है। यह नाम न बताकर सदन को गुमराह कर रहे हैं। **(व्यवधान)** चेयरमैन साहब आप अनुभवी हैं, आपकी इतनी आयु हो गयी है, आप इनको नाम देने के लिए कह सकते हैं। **(व्यवधान)**

SHRI JAGESH DESAI : He is giving.

SHRI AJAY SINGH : He has not understood me. The names are—M/s. Universal Refrigeration Company, Calcutta, M/s. Vidhi Sindhi Engineering Company, Calcutta, M/s T. S. Sales Corporation, Calcutta, M/s Industrial Enterprises (India), Calcutta, M/s. S.K. Sales Corporation, Calcutta, National Electrical Stores, Calcutta, Metro Company Services, Calcutta, Ultra Mechanical Engineering Company, Calcutta, Trade Centre Calcutta, United Enterprises, Calcutta, Anil Motors, Calcutta and A.K. Enterprises, Calcutta.

**श्री सभापति :** यह आपने नहीं बताया कि चांदी की पटरी पर कब तक रेल चलनी शुरू होगी?

SHRI CHATURANAN MISHRA : He wanted to know whether they have been blacklisted.

MR. CHAIRMAN : They will do if after investigation. He has said it.

SHRI RAJ MOHAN GANDHI : The hon. Minister for Railway has said that there is a policy of transferring officers after four years stay at one place. Will he be kind enough to inform the House whether a representation has been received from the Federation of Railway Officers regarding their serious dissatisfaction with the promotional policy in the Railways ? If so, what action is the Government taking ?

SHRI GEORGE FERNANDES : It does not arise out of this-

**श्री राज मोहन गान्धी :** ट्रांसफर और प्रमोशन के बारे में पूछा है। उन्होंने ट्रांसफर की बात की थी ... **(व्यवधान)**

**श्री सभापति :** उन्होंने करप्शन को रोकने के लिए ट्रांसफर की बात की थी। यह तो करप्शन का सवाल है।

**कृषि वैज्ञानिकों का विदेश में प्रशिक्षण**

***345. श्री शंकर दयाल सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विशेष प्रशिक्षण के लिये कितने वैज्ञानिक को विदेश भेजा था;

(ख) क्या अनेक कृषि वैज्ञानिकों ने इस संबंध में चयन समिति के बारे में अपना असंतोष व्यक्त किया है और सरकार को हाल में कोई ज्ञापन दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**उप-प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) :** (क) श्रीमान, पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विशेष प्रशिक्षण के लिए 834 वैज्ञानिकों को विदेश भेजा था।

(ख) सरकार को चयन प्रक्रिया के विरुद्ध कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**श्री शंकर दयाल सिंह :** सभापति जी, सभी इस बात को जानते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि के मामले में और अनुसंधान के क्षेत्र में देश व्यापी प्रभावी संस्थान है और इसके लिए मंत्री महोदय ने स्वयं बयान दिया है और विवरण भी प्रस्तुत किया है, उसमें बताया है कि तीन वर्षों में 834 कृषि वैज्ञानिक बाहर के देशों में भेजे गये; ये लगभग तीन सौ कृषि वैज्ञानिक प्रति वर्ष होते हैं। प्रतिदिन एक कृषि वैज्ञानिक विदेश में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि ये जो तीन वर्ष में 834 कृषि वैज्ञानिक बाहर भेजे गये उनमें से कितने ऐसे थे जो विदेशों के द्वारा हमारे देश से भेजे गये और जो निमंत्रण आते हैं उस पर कितने भेजे गये और ऐसे कितने वैज्ञानिक हैं जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के खर्चे पर बाहर भेजे गये ? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि इनमें से कितने ऐसे कृषि वैज्ञानिक हैं जिन्होंने प्रशिक्षण के बावजूद रिजाइन कर दिया और दूसरे काम में चले गये ? उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

**कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नितीश कुमार) :** सभापति महोदय, जो 834 वैज्ञानिक बाहर गये उनमें वे कई प्रकार से गये जिसमें बाहर से बुलावा भी शामिल है। इसका विस्तृत ब्यौरा कम से कम आठ पृष्ठों का है जो मैं आप चाहें तो पढ़ देता हूं। परन्तु मैं एक फीगर बता देता हूं कि पिछले तीन वर्षों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या फलोशिप